PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 027
दि. 27.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तीन राज्यों को तत्काल कार्रवाई और निगरानी मजबूत करने के निर्देश

नई दिल्ली में मंगलवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में बढ़ते अवैध रेत खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान—की सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि संरक्षित क्षेत्रों में अवैध खनन पर तुरंत प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो इसका गंभीर पर्यावरणीय और कानूनी परिणाम हो सकता है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था से जुड़ा है, बल्कि देश के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा से भी सीधा संबंध रखता है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई के दौरान चंबल क्षेत्र में लगातार हो रही अवैध रेत ढुलाई और खनन गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए तथ्य, जिनमें बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से रेत ढुलाई की बात कही गई है, यदि सही पाए जाते हैं तो यह प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत को दर्शाते हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि सरकारों द्वारा दायर हलफनामों में दिए गए दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते, तो यह गंभीर स्थिति को जन्म देता है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को निर्देश दिया कि अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को तुरंत मजबूत किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और आधुनिक निगरानी व्यवस्था को युद्धस्तर पर स्थापित किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि छह महीने के भीतर पूरी निगरानी प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय और प्रभावी हो। अदालत ने कहा कि केवल नीतिगत घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई जरूरी है ताकि अवैध खनन नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि फर्जी नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि कार्रवाई केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस पूरे अवैध खनन नेटवर्क से जुड़े वाहन मालिकों, ठेकेदारों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जाए। इस तरह की गतिविधियों को संगठित अपराध की तरह देखा जाना चाहिए, जिसमें सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वन विभाग और फील्ड स्तर के कर्मचारियों की सुरक्षा और संख्या को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कई क्षेत्रों में वन रक्षकों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को कमजोर करती हैं। इसलिए राज्यों को निर्देश दिया गया कि खाली पड़े वन रक्षक पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और फील्ड स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे, तो अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं हो पाएगा।

इस मामले में अदालत ने स्थानीय प्रशासन को यह भी सुझाव दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल प्रतिबंधात्मक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान के लिए स्थानीय समुदायों को संरक्षण, वृक्षारोपण, इको-टूरिज्म और निगरानी गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। इससे न केवल अवैध खनन पर नियंत्रण होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार भी मिल सकेगा।

चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जिस पर यह पूरा मामला केंद्रित है, लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और रेड-क्राउन रूफ टर्टल का प्रमुख आवास माना जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, अवैध रेत खनन इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, क्योंकि इससे नदियों का प्रवाह प्रभावित होता है, जलजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है और पूरे क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले पर 17 अप्रैल को सुनवाई करते हुए चिंता जताई थी और कहा था कि अदालत इस तरह की पर्यावरणीय तबाही पर मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने अपने रुख को और सख्त करते हुए तीनों राज्यों को समन्वित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि आगे भी लापरवाही जारी रहती है, तो सख्त न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तीनों राज्य सरकारें अदालत के निर्देशों को कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ लागू करती हैं।

दलित वोट बैंक पर कांग्रेस का नया फोकस राहुल गांधी ने माना पुरानी रणनीति में रही कमियां

नई दिल्ली में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक रणनीति को लेकर एक अहम बैठक के दौरान पार्टी की भविष्य की दिशा पर बड़ा संकेत मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि अब पार्टी दलित समाज की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका को और अधिक मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी। इस बैठक को कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें न केवल संगठनात्मक पुनर्गठन की बात हुई, बल्कि अतीत की गलतियों पर भी आत्ममंथन किया गया।

बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए यह स्वीकार किया कि 1980 और 1990 के दशक में कांग्रेस दलित समाज के हितों को लेकर अपेक्षित प्रभावी कदम नहीं उठा पाई थी। उन्होंने कहा कि यदि उस समय सही नीतिगत निर्णय लिए गए होते, तो देश में जाति आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय इस रूप में नहीं होता और दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से दूरी नहीं बनाता। इस टिप्पणी को पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब इस तरह की सार्वजनिक आत्मालोचना इतने स्पष्ट शब्दों में सामने आई है।

राहुल गांधी ने बैठक में यह भी कहा कि कांग्रेस को अब अपनी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार दलित समाज केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि देश की सामाजिक संरचना का एक मजबूत स्तंभ है, जिसकी भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में पार्टी संगठन में दलित नेतृत्व को अधिक अवसर दिए जाएंगे और नीति निर्माण में उनकी भूमिका को भी बढ़ाया जाएगा।

बैठक में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आया कि राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की खुले तौर पर सराहना की। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने दलित समाज में राजनीतिक चेतना और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके प्रयासों के कारण ही दलित राजनीति एक संगठित शक्ति के रूप में उभरी, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा को प्रभावित किया।

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ओर क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर दलित और वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बयान को आने वाले चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव पर केंद्र का बड़ा कदम, जस्टिस नावलेकर की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति

नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़ा कदम उठाते हुए अवैध प्रवासन और असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य पूरे देश में अवैध घुसपैठ, अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलावों और उनसे उत्पन्न होने वाले सामाजिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा संबंधी प्रभावों का गहन अध्ययन करना है।

गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि देश में अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से होने वाले असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल सांख्यिकीय बदलाव नहीं हैं, बल्कि वे किसी भी राष्ट्र की वर्तमान और भविष्य की स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से जनसांख्यिकीय बदलावों पर उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी और अब उस घोषणा को अमल में लाया गया है। सरकार द्वारा गठित इस समिति में प्रशासन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की नियुक्ति की गई है, जबकि

इसके अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के जनगणना आयुक्त भी समिति का हिस्सा होंगे, जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि जनसांख्यिकीय बदलाव केवल जनसंख्या वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता और जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान जैसे संवेदनशील विषयों से भी जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ और अप्राकृतिक आबादी वृद्धि के कारण सामाजिक संरचना में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव कानून व्यवस्था और स्थानीय संसाधनों पर पड़ सकता है। सरकार के अनुसार यह समिति पूरे भारत में धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का अध्ययन करेगी। साथ ही यह भी जांच करेगी कि किन कारणों से कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसका स्थानीय प्रशासन, रोजगार, सामाजिक समरसता तथा सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक समिति को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह ऐसे परिवर्तनों के पीछे मौजूद संभावित कारणों की पहचान करे और उनके समाधान के लिए समयबद्ध तथा व्यावहारिक सुझाव सरकार को सौंपे। इसमें सीमा क्षेत्रों में अवैध प्रवासन, नकली दस्तावेजों के जरिए पहचान प्राप्त करने, सामाजिक ढांचे में बदलाव और संसाधनों पर बढ़ते दबाव जैसे पहलुओं का भी अध्ययन शामिल होगा।

जनकल्याण की नई पहल: बंगाल में सस्ती थाली, महिला सशक्तिकरण और नशामुक्ति पर सरकार का बड़ा फोकस

कोलकाता में मंगलवार को प्रशासनिक हलकों में उस समय हलचल बढ़ गई जब पश्चिम बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ी एक बड़ी जनकल्याणकारी योजना की जानकारी सामने आई। राज्य सरकार ने एक साथ कई ऐसे फैसलों की घोषणा की है, जिनका सीधा संबंध आम जनता, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार से बताया जा रहा है। इन घोषणाओं के केंद्र में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता, गरीबों के लिए बेहद सस्ती दर पर भोजन और शराब की बिक्री को लेकर कड़े नियम शामिल हैं। इन सभी योजनाओं को राज्य में सुशासन और सामाजिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य के शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर हुई बैठक के बाद यह जानकारी सामने आई कि सरकार एक नई योजना 'अन्नपूर्णा योजना' की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये

की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम होंगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू करने की बात कही गई है और इसे सरल तथा पारदर्शी रखने का आश्वासन भी दिया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना भी है। राज्य सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो पूरे परिवार और समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी की जा रही है ताकि समाज के हर वर्ग की महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सके।

इसके साथ ही सरकार ने आम जनता के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो सीधे तौर पर दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। राज्य में गरीब और मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मात्र 5 रुपये में मछली और चावल की थाली उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में लगभग 400 विशेष कैंटीनें स्थापित करने की तैयारी है, जहां सप्ताह में दो दिन यह सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहतकारी मानी जा रही है, जिनके लिए रोजाना पौष्टिक भोजन जुटाना चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार की ओर से बताया गया है कि इन कैंटीनों में भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बेहद कम कीमत के बावजूद लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले। मछली-चावल जैसी पारंपरिक थाली को इस योजना में शामिल करना राज्य की सांस्कृतिक खाद्य परंपरा को भी दर्शाता है। प्रशासन का मानना है कि यह कदम न केवल भूख और कुपोषण को कम करने में सहायक होगा, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास साबित होगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने शराब की बिक्री और दुकानों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इससे सामाजिक वातावरण अधिक स्वस्थ और सुरक्षित बनेगा। इस नीति के लागू होने के बाद कई इलाकों में मौजूदा शराब दुकानों की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई भी की जाएगी। इस निर्णय को सामाजिक सुधार और जनस्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि इन तीनों घोषणाओं का सीधा प्रभाव राज्य के अलग-अलग वर्गों पर पड़ेगा। जहां एक ओर महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग के लिए सस्ती भोजन योजना राहत लेकर आएगी। इसके साथ ही नशा नियंत्रण संबंधी नीति सामाजिक अनुशासन और युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम मानी जा रही है। हालांकि इन घोषणाओं के राजनीतिक प्रभावों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आगामी चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये योजनाएं बड़े वोट बैंक को प्रभावित करती हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य केवल और केवल जनकल्याण है और इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल राज्य में इन योजनाओं को लेकर उत्सुकता का माहौल है। लोग यह जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अन्नपूर्णा योजना का वास्तविक क्रियान्वयन कैसे होगा, 5 रुपये वाली थाली किन क्षेत्रों में सबसे पहले शुरू की जाएगी और शराब बिक्री पर नए नियम कितनी सख्ती से लागू होंगे। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इन योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी।

संपादकीय

एक और मिल्खा सिंह

एक प्रेरक कहावत है कि सुबह जिसकी हुई, सचमुच वो सारी रात नहीं सोया होगा। आज जब हम पंजाब के पुत्र गुरिंदरवीर सिंह की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की बात कर रहे हैं तो हमें इस मुकाम तक पहुंचने के उसके संघर्ष को भी याद करना चाहिए। कोई भी कामयाबी रातों-रात नहीं मिलती। महज 10.09 सेकंड में सौ मीटर की रेस पूरी करने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने, निस्संदेह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर देशवासियों को गर्व करने का मौका दिया है। निर्विवाद रूप से उनके भारत के सबसे तेज धावक बनने की कहानी महज चंद घड़ियों की बदौलत नहीं नापी जा सकती। गांव की धूल से भरी सड़कों में उनका अभ्यास, प्रशिक्षण मैदानों में पसीने के साथ थका देने वाला सफर और संसाधन के अभावों से जूझकर ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वहीं इस कामयाबी में उनके परिवार का खामोश त्याग भी शामिल है, जो उनकी कामयाबी के बाद ही सुर्खियों में नजर आ पाया है। जालंधर के निकट स्थित पटियाल गांव के स्प्रिंट किंग गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप में जब सौ मीटर की दौड़ 10.09 सेकेंड में पूरी की तो इस मुकाम तक पहुंचने वाले वे पहले भारतीय थे। एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इस इतिहास को रचकर गुरिंदरवीर सिंह देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में शामिल हो गए हैं। इस सफलता का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस कामयाबी के बाद वे स्वतः ही राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने के हकदार हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में एक और पदक जीतने की उम्मीद फिर से जगा दी है। उल्लेखनीय है कि स्प्रिंट किंग गुरिंदरवीर का सौ मीटर की दौड़ पूरी करने का यह समय इस सीजन में एशिया का दूसरा सबसे तेज समय है। वे जापान के फुकुतो कोमुरो से महज .01 सेकेंड ही पीछे रहे हैं। विश्वास करना चाहिए कि भविष्य में गुरिंदरवीर सिंह नये मुकाम हासिल करेंगे।

यह विरोधाभास ही है कि जब कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करता है तो हम उसे पलक-पावड़ों पर बैठा देते हैं। मान-सम्मान और पुरस्कार देते हैं। लेकिन यदि छोटी उम्र में ही प्रतिभा को पहचान करके उसे पर्याप्त संसाधन व प्रशिक्षण प्रदान करें तो देश में कई गुरिंदरवीर तैयार हो सकते हैं। गुरिंदरवीर सिंह की इस कामयाबी के पीछे कई प्रेरणादायक कहानियां भी निहित हैं। उनका मानवीय पहलू हमारे समाज की सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। उनके पिता ने अपने बेटे को दौड़ के अभ्यास हेतु भेजने के लिये किश्तों में एक पुराना स्कूटर खरीदा था। जो बताता है कि एक तरफ क्रिकेट खिलाड़ियों पर लाखों-करोड़ों वारे जाते हैं तो दूसरी ओर परंपरागत खेलों से जुड़े खिलाड़ियों का संघर्ष कितना बड़ा है। वहीं गुरिंदरवीर सिंह को तराशने-निखारने की यात्रा में भारतीय नौसेना के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिसने गुरिंदरवीर सिंह को ट्रैक पर उत्कृष्ट सफलता हासिल करने हेतु संबल दिया। निस्संदेह, गांव-कस्बों से निकलने वाली प्रतिभाओं की कामयाबी के पीछे सीमित संसाधनों वाले माता-पिता के दृढ़ संकल्प और त्याग की कहानी छिपी रहती है। गुरिंदरवीर सिंह जैसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी के पीछे एक परिवार शिद्दत के साथ खड़ा होता है, जो उसके सुनहरे भविष्य के लिये अपनी सुख-सुविधा, बचत व आर्थिक सुरक्षा तक त्याग कर देता है। गुरिंदरवीर सिंह के दिल में गांव और साधारण परिवारों में पले-बढ़े बच्चों के संघर्ष के प्रति खासा सम्मान है। वे उन हजारों नवोदित खिलाड़ियों के लिये प्रेरणापुंज हैं जो अपनी पृष्ठभूमि वाले एक खिलाड़ी को राष्ट्रीय फलक पर चमकता देख रहे हैं। निश्चय ही इस कामयाबी से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक कामयाबी से पहले जालंधर की महिला खिलाड़ियों से उनका संवाद बेहद सहज-सरल व प्रेरणादायक था कि तुम्हें भी एकदिन यहां पहुंचना है। निश्चय ही उनका यह कथन नवोदित प्रतिभाओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। निस्संदेह, विगत में भी पंजाब ने कई ऐसे खेल नायकों को जन्म दिया, जिन्होंने अभावों से जूझते हुए दृढ़ संकल्प से कामयाबी की नई इबारत लिखी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से लेकर जालंधर एक्सप्रेस गुरिंदरवीर की कामयाबी उसकी गवाह है। जो नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने को प्रेरित करती है।

पर्यावरण पर गंभीर है प्रिंट मीडिया, टीवी नहीं

> “ पर्यावरणीय आंदोलनों से जुड़े घटनाक्रम राष्ट्रीय-क्षेत्रीय समाचार पत्र अधिक संतुलित, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि टीआरपी-आधारित प्रतिस्पर्धा के कारण टीवी समाचार चैनल राजनीतिक बहस, चुनावी बयानबाजी, अपराध व मनोरंजक खबरों को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण, जल संकट, जंगलों में आग, असमय वर्षा, हिमालयी भू-स्खलन और शहरी पर्यावरणीय अव्यवस्था जैसी समस्याओं ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। साथ ही, जंगल कटान, खनन परियोजनाएं, नदी जोड़ो योजनाएं, आदिवासी विस्थापन और जैव विविधता पर बढ़ते खतरे देशभर में व्यापक जनआंदोलनों का कारण बने हैं।

पर्यावरणीय आंदोलनों की मीडिया कवरेज को लेकर गंभीर प्रश्न उठे हैं। राष्ट्रीय-क्षेत्रीय समाचार पत्र इन मुद्दों को अधिक संतुलित, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि टीआरपी-आधारित प्रतिस्पर्धा के कारण टीवी समाचार चैनल राजनीतिक बहस, चुनावी बयानबाजी, अपराध व मनोरंजक खबरों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। चूंकि पर्यावरणीय विषय गहन शोध, फील्ड रिपोर्टिंग और दीर्घकालिक विश्लेषण की मांग करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन्हें अपेक्षित समय-संसाधन नहीं मिले।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी केन–बेतवा रिवर लिंक परियोजना लगभग 44 हजार करोड़ रुपये की एक बड़ी जल संसाधन योजना है। इसका उद्देश्य केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा बेसिन तक पहुंचाकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना है। हालांकि, परियोजना को लेकर कई गंभीर चिंताएं भी सामने आई हैं, जिनमें हजारों लोगों का विस्थापन, वन भूमि का जलमग्न होना तथा पन्ना टाइगर रिजर्व की जैव विविधता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। वहीं छतरपुर और पन्ना जिलों में प्रभावित ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों ने विरोध के विभिन्न प्रतीकात्मक तरीके अपनाए। प्रदर्शनकारियों ने संदेश देने का प्रयास किया कि विस्थापन उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को समाप्त कर देगा।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को मानवीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विस्तारपूर्वक कवर किया। दूसरी ओर, अधिकांश टीवी चैनलों पर यह मुद्दा सीमित समाचार पैकेजों तक सिमटता दिखाई दिया।

इसी प्रकार ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में प्रस्तावित वेदांता समूह की बॉक्साइट खनन परियोजना के खिलाफ स्थानीय आदिवासी समुदायों का विरोध मीडिया कवरेज में भिन्नता को दर्शाता है। जहां इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, वहीं टीवी चैनलों ने मुख्यतः सिजिमाली पहाड़ियों में सड़क निर्माण के दौरान हुई पुलिस–आदिवासी झड़प को अधिक प्रमुखता दी। इसके विपरीत भूमि अधिकार, जल स्रोतों, वन संरक्षण और विस्थापन जैसे मूलभूत मुद्दे अपेक्षाकृत कम उभरे। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के विरोध में चल रहा विरोध प्रदर्शन भी पर्यावरणीय पत्रकारिता की उपेक्षा का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। यह क्षेत्र भारत के सबसे घने जंगलों में से एक है और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। स्थानीय आदिवासी समुदाय लंबे समय से खनन परियोजनाओं के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों पेड़ों पर खनन परियोजनाओं का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर इस संघर्ष को लगातार कवरेज नहीं मिली।

इसी प्रकार राजस्थान के शाहबाद वन क्षेत्र में पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार आवाज उठा रहे हैं। अरावली क्षेत्र और वन संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा डिजिटल मीडिया संस्थानों ने इस संघर्ष को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और आदिवासी अधिकारों के संदर्भ में प्रमुखता से प्रकाशित किया।

हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते पर्यावरणीय संकट को लेकर 'हिमालय है तो हम हैं' अभियान के तहत पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्टों ने भी आवाज़ उठाई। इस अभियान का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अंधाधुंध निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, जलविद्युत परियोजनाओं और अनियंत्रित पर्यटन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाना है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित 'जल सहेली' अभियान भी पर्यावरणीय जनभागीदारी का उल्लेखनीय उदाहरण है, लेकिन मुख्यधारा टीवी चैनलों पर इसकी उपस्थिति सीमित रही।

मीडिया विश्लेषकों मानते हैं कि टीवी चैनलों में 'टीआरपी-चालित पत्रकारिता' के कारण पर्यावरणीय रिपोर्टिंग कमजोर हुई है। पर्यावरणीय मुद्दे प्रायः जटिल, दीर्घकालिक और शोध-आधारित रिपोर्टिंग की मांग करते हैं, जबकि टीवी मीडिया त्वरित दृश्य प्रभाव और राजनीतिक टकराव को प्राथमिकता देता है। इसके कारण पर्यावरणीय सरोकारों व विस्थापन के मुद्दे मीडिया एजेंडा में अपेक्षाकृत पीछे रह जाते हैं।

मीडिया अध्ययन के अनुसार यह स्थिति 'इश्यू हायरार्की' और 'मीडिया प्रायोरिटाइजेशन' का उदाहरण है, जहां दीर्घकालिक जनहित के मुद्दों की तुलना में तात्कालिक राजनीतिक सामग्री को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता मंचों ने पर्यावरणीय मुद्दों को नई दृश्यता प्रदान की है। निस्संदेह, देश आज जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब मीडिया की भूमिका केवल सूचना प्रसारित करने तक सीमित नहीं रह सकती।

प्रेरणा

जब भारतीय साड़ी ने ओलंपिक कोर्ट पर दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया

वर्ष 1924 का ओलंपिक खेल इतिहास के उन पलों में शामिल है, जब केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा ही नहीं, बल्कि देशों की संस्कृति और पहचान भी दुनिया के सामने उभरकर आई थी। यूरोप और अमेरिका के खिलाड़ी आधुनिक खेल परिधानों में अपनी-अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे थे। टेनिस कोर्ट पर पश्चिमी पहनावे का दबदबा था और खेल को भी एक तरह से आधुनिक पश्चिमी जीवनशैली का प्रतीक माना जाता था। उसी दौरान जब मिश्रित युगल टेनिस स्पर्धा के लिए भारत की एक महिला खिलाड़ी कोर्ट पर पहुंचीं, तो पूरा स्टेडियम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। दर्शकों की आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। कारण यह था कि वह महिला खिलाड़ी किसी विदेशी खेल पोशाक में नहीं, बल्कि भारतीय साड़ी में थीं। वह खिलाड़ी थीं मेहरबाई टाटा, जो प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र सर दोराबजी टाटा की पत्नी थीं।

उस समय दुनिया भारत को एक गुलाम देश के रूप में देखती थी। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों को अक्सर पिछड़े और कमजोर समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। भारतीय महिलाओं की छवि भी दुनिया के सामने सीमित दायरे में दिखाई जाती थी। लेकिन मेहरबाई टाटा ने ओलंपिक के उस मंच पर अपनी उपस्थिति से पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने केवल टेनिस नहीं खेला, बल्कि भारतीय संस्कृति, आत्मविश्वास और नारी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने विदेशी दर्शकों और मीडिया को भी प्रभावित कर दिया।

टेनिस एक ऐसा खेल है, जिसमें गति, संतुलन, फुर्ती और मानसिक एकाग्रता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उस दौर में महिलाएं आमतौर पर स्कर्ट और हल्के खेल परिधान पहनकर खेलती थीं ताकि तेजी से दौड़ सकें। ऐसे में साड़ी पहनकर टेनिस खेलना किसी असंभव चुनौती से कम नहीं था। लेकिन मेहरबाई टाटा ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। कोर्ट पर उनकी तेज सर्विस, सटीक शॉट्स और चपलता को देखकर दर्शक दंग रह गए। विदेशी अखबारों ने उनकी तस्वीरें और समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए। लोग चर्चा करने लगे कि भारतीय महिलाएं केवल परंपरा की प्रतीक नहीं, बल्कि प्रतिभा और साहस की भी मिसाल हैं।

मेहरबाई टाटा का यह साहस केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था। उस दौर में भारत का सामाजिक वातावरण महिलाओं के लिए बहुत सीमित था। अधिकांश महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था। शिक्षा, खेल और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बेहद कम थी। समाज में यह धारणा गहरी थी कि महिलाओं का मुख्य कार्य केवल परिवार संभालना है। ऐसे समय में एक भारतीय महिला का अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उतरना ही अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन मेहरबाई ने इससे भी आगे बढ़कर भारतीय संस्कृति को गर्व के साथ दुनिया के सामने रखा।

उन्होंने यह साबित किया कि आधुनिकता अपनाने का अर्थ अपनी जड़ों और परंपराओं को त्याग देना नहीं है। साड़ी पहनकर खेलना उनके लिए केवल पहनावे का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह भारतीय पहचान के सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति किसी भी आधुनिक मंच पर सम्मानपूर्वक खड़ी हो सकती है। मेहरबाई टाटा खेलों के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में भी अत्यंत सक्रिय थीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। विशेष रूप से बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उस समय कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना सामान्य माना जाता था, जिससे उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता दोनों समाप्त हो जाती थीं। मेहरबाई ने इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया।

उनका व्यक्तित्व भारतीय समाज में एक नई सोच का प्रतीक बन गया। वे आधुनिक विचारों वाली महिला थीं, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने यह दिखाया कि एक महिला शिक्षित, आधुनिक और आत्मविश्वासी होते हुए भी अपनी परंपराओं पर गर्व कर सकती है। यही कारण था कि वे उस समय भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बन गईं।

आज जब खेलों में ग्लैमर और फैशन का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है, तब मेहरबाई टाटा की कहानी एक अलग संदेश देती है। उन्होंने यह साबित किया कि खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान उसका समर्पण, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है, न कि केवल उसका पहनावा। साड़ी में टेनिस खेलते हुए उन्होंने दुनिया को यह एहसास कराया कि भारतीय परंपरा किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान का प्रतीक है।

उनकी यह विरासत आज भी भारतीय महिलाओं को प्रेरित करती है। आधुनिक भारत में महिलाएं खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे ओलंपिक हो, विश्व कप हो या अन्य बड़ी प्रतियोगिताएं, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। लेकिन इस सफलता की नींव उन महिलाओं ने रखी थी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस दिखाया। मेहरबाई टाटा उन्हीं अग्रणी महिलाओं में शामिल थीं।

उनकी कहानी केवल खेल जगत की प्रेरणा नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की शक्ति का भी उदाहरण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय महिलाएं अपनी पहचान और परंपराओं के साथ भी विश्व मंच पर सफल हो सकती हैं। ओलंपिक के उस टेनिस कोर्ट पर साड़ी में खड़ी मेहरबाई टाटा केवल एक खिलाड़ी नहीं थीं, बल्कि वे भारत की आत्मा, भारतीय नारी के साहस और सांस्कृतिक गौरव की जीवंत प्रतीक थीं। उनका जीवन आज भी यह संदेश देता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है।

अमेरिका-ईरान युद्ध से महंगाई के कारण आमजन प्रभावित

भले ही 1970 के तेल संकट जैसे हालात होने की संभावना ना हो या 2008 जैसी वित्तीय मंदी के हालात ना हो फिर भी एक बात साफ है कि अमेरिका-ईरान के बीच करीब तीन माह से चल रहे युद्ध के नकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। चाहे एशिया के देश हो या फिर योरोपीय देश सभी केवल वैश्विक तनाव ही नहीं अपितु ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने से बढ़ते दामों को रोकने में विफल ही हो रहे हैं। पिछले दस-पन्द्रह दिनों में ही हमारे देश में पेट्रोल- एलपीजी-सीएनजी-पीएनजी के दामों में एक बार नहीं अपितु तीन बार बढ़ोतरी हो चुकी है। हांलाकि वर्तमान हालातों में सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाये या आंदोलन-प्रदर्शन करें पर अंतरराष्ट्रीय हालातों से आंख नहीं मूंदनी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमजन से आग्रह को भी इसी संदर्भ में सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए। वैसे भी जब संकट का दौर हो और उस संकट के लिए हम या हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं हो तो फिर देश में नकारात्मक माहौल बनाने के स्थान पर सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का नहीं अपितु सभी राजनीतिक दलों का दायित्व हो जाता है। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ईंधन संकट का बड़ा कारण अमेरिका-ईरान युद्ध ना होकर अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण हार्मुज संकट बन गया है। हार्मुज के रास्ते से ही कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और तनाव के चलते हार्मुज जनडमरुमध्य रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है इससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यह तो वैकल्पिक उर्जा के रुप में देश में सोलर, विण्ड एनर्जी के क्षेत्र में पिछले सालों में योजनावद्ध तरीके से तेजी से और बेहतर काम हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री इलेक्ट्रोनिक वाहनों के उपयोग या सोलर एनर्जी के उपयोग पर खुले तौर पर आग्रह करने की स्थिति में है। नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में देश में तेजी से काम हुआ है और हो रहा है जो एक हद तक संकट को कम करने में सहायक बन रहा है। आज की दुनिया आइसोलेट दुनिया नहीं है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ी है। कहीं से ईंधन के लिए तो कहीं से खाद्यान्न, कहीं दवा, कहीं अन्य किसी वस्तु के लिए निर्भरता बढ़ी है। युद्ध के चलते इंटरनेशनल लोजिस्टिक सेवाएं प्रभावित हुई है। जहां तक देश की ही बात की जाएं तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि के कीमत में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा है। सीधी सी बात है जब आवागमन महंगा होगा चाहे वह आम आदमी, सार्वजनिक क्षेत्र या लोजिस्टिक का हो तो उसका सीधा सीधा वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा ही। यही कारण है ईंधन यानी तेल के भावों में बढ़ोतरी के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। इसके साथ ही आयात पर निर्भर वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक तेल का प्रश्न है देश में खाद्य तेल और अखाद्य तेल दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य तेलों में भी आयात पर निर्भरता अधिक है। लाख प्रयासों के बावजूद तिलहन मिशन से तिलहनों का उत्पादन तो बढ़ा है पर अभी विदेशी निर्भरता बनी हुई ही है। इसी तरह से अन्य वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक सेवा क्षेत्र का प्रश्न है स्वीगी-जोमेटो आदि सेवा प्रदाताओं ने पिछले दिनों में अपने दामों में 16 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने प्लानों को रिवाइज किया हैं तो उबेर-ओला जैसे सेवा प्रदाताओं ने किराया बढ़ा दिया है। हो तो यहां तक रहा हैं कि बैंकों द्वारा जमाओं पर ब्याज दर में कमी लाना शुरु कर दिया है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोजिस्टिक लागत बढ़ेगी तो उसका असर सभी वस्तुओं में देखने को मिलेगा। भारत सरकार वेनेजुएला से वैकल्पिक तरीके से कच्चे तेल लाने का प्रयास कर रही है तो अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। पर यह साफ हो जाना चाहिए कि कच्चे तेल की आपूर्ति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक पूरी तरह से संकट समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इन वैश्विक हालातों के पीछे अमेरिका-ईरान की हठधर्मिता ही है। अमेरिका-इजरायल ने ईरान से लड़ाई शुरु करते समय रुस यूक्रेन युद्ध के हालातों से सबक नहीं लिया। रुस के सामने यूक्रेन पिद्दी सा देश होने के बावजूद आज तीन साल से भी अधिक समय होने के बावजूद निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है। पर अमेरिका ने यह सोचा था कि दो-तीन दिन में ही ईरान को घुटने टिकवा देंगे और यही अमेरिका की नासमझी रही। मानो या ना मानो पर वास्तविकता यह है कि आज अमेरिका के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का संकट आ गया है और यही कारण है कि अंदरखाने अमेरिका और ट्रंप किसी भी तरह से सीज फायर के लिए प्रयासरत है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि युद्ध में नुकसान अमेरिका को ही अधिक हो रहा है। ईरान तो अपने घर से लड़ रहा है और उसके निशाने पर आसपास के देश है। ऐसे में स्टेक तो अमेरिका-इजरायल का ही हो जाता है। इसके अलावा एक बात और समझनी होगी कि ट्रंप 2 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आये दिन तुगलकी फरमान जारी कर दुश्मन ही दुश्मन बनाएं है। गली के गुंडे जैसी पहचान बन गई है ट्रंप की तो दूसरी और अमेरिका के ही अधिकांश लोगों का भरोसा ट्रंप ने खो दिया है। ऐसे में सम्मानजनक सीजफायर ही अमेरिका के लिए अब इस संकट से निकलने का रास्ता रह गया है और इसके लिए ही अंदरखाने प्रयास जारी है।

अभियान

पूर्ण चंद्र की दिव्य आभा में जागृत होता अध्यात्म और जीवन का उजास

सनातन धर्म में समय को केवल दिनों और महीनों की गणना तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि प्रत्येक तिथि को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य चेतना से जोड़ा गया है। इन्हीं पवित्र तिथियों में पूर्णिमा का विशेष स्थान है। पूर्णिमा वह क्षण है, जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं के साथ पूर्ण तेजस्विता में आकाश में प्रकट होता है और अपनी शीतल चांदनी से संपूर्ण सृष्टि को आलोकित कर देता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार हर हिंदी महीने का समापन पूर्णिमा तिथि पर होता है और इस प्रकार वर्ष भर में बारह पूर्णिमाएं आती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। इस वर्ष ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत 30 मई, शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि पुरुषोत्तम मास अथवा अधिकमास में आती है, तब उसका पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दिन पूजा-पाठ, स्नान-दान, जप-तप और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है।

पूर्णिमा केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मन, विचार और चेतना से भी गहराई से जुड़ी हुई मानी जाती है। चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है और पूर्णिमा की रात को उसकी पूर्ण कलाएं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रकृति में दिव्य कंपन बढ़ जाते हैं और साधना करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक ऊर्जा तथा आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति होती है। इसीलिए सनातन परंपरा में पूर्णिमा को अत्यंत शुभ माना गया है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव तथा चंद्रदेव की पूजा का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है।

ज्येष्ठ पूर्णिमा का संबंध केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय आस्था और परंपराओं का भी जीवंत प्रतीक है। इसी दिन से हजारों श्रद्धालु पवित्र गंगाजल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का यह अद्भुत दृश्य भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की महानता को दर्शाता है। श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्गों से होकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं और उनके हाथों में गंगाजल का कलश केवल जल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और तपस्या का प्रतीक बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, अलकनंदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग इन पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय सभी तीर्थों तथा पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। सनातन मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भी पुण्यफल की प्राप्ति होती है।

पूर्णिमा का यह पर्व मनुष्य को केवल बाहरी शुद्धता ही नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का भी संदेश देता है। इस दिन सात्विकता को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर व्यक्ति को क्रोध, ईर्ष्या, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के प्रति दुर्भावना रखनी चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहकर सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मन, वचन और कर्म की पवित्रता ही इस दिन के व्रत और पूजा का वास्तविक आधार मानी गई है।

सनातन धर्म में वट वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए इसकी पूजा करती हैं। इसी प्रकार इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और सुनाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक सत्यनारायण कथा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं।

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, फल और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दान केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि करुणा, सहानुभूति और मानवता का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से किया गया दान पितरों को शांति प्रदान करता है और दानकर्ता को विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन योग्य व्यक्ति को श्रद्धा से दान करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तक हो सकती है।

धार्मिक परंपराओं में सूर्य और चंद्रमा दोनों को विशेष स्थान दिया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देते हुए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य को जीवन, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य आराधना से व्यक्ति के जीवन से अज्ञान और दुर्भाग्य का अंधकार दूर होता है तथा आत्मविश्वास और सकारात्मकता का विकास होता है।

वहीं रात्रि में चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में प्रकट होता है और उसकी शीतल चांदनी वातावरण में अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस रात चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है या जो मानसिक अशांति, भय और अस्थिरता से परेशान रहते हैं, उनके लिए चंद्र पूजा अत्यंत लाभकारी मानी गई है।

इस रात चंद्रमा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि चंद्र मंत्रों का जाप करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। पूर्णिमा की उजली चांदनी केवल आकाश को ही प्रकाशित नहीं करती, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को भी दूर करने का संदेश देती है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का यह पर्व वास्तव में मनुष्य को जीवन की सच्ची दिशा दिखाने वाला उत्सव है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड का अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, दया, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का महापर्व है। यह दिन मनुष्य को यह सिखाता है कि जैसे पूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर ज्ञान, करुणा और सत्य का प्रकाश जगाना चाहिए। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वह प्रकृति, ग्रहों, ऋतुओं और आध्यात्मिक चेतना को एक सूत्र में जोड़कर जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात की चीनी सहकारी समितियों तथा गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

▸▸ राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान चीनी समितियों द्वारा किसानों को चुकाई गई गन्ने की कीमतों को दी आधिकारिक मंजूरी : सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ इस निर्णय से सहकारी चीनी समितियों पर 1599 करोड़ रुपए का बोझ कम होगा, दो लाख से अधिक गन्ना किसानों और सहकारी समितियों को मिलेगी बड़ी राहत

▸▸ मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने चीनी सहकारी समितियों और किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी , केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र, विशेषकर गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इस निर्णय की जानकारी देते हुए कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान चीनी समितियों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाई गई कीमतों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से गुजरात की चीनी सहकारी समितियों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का बड़ा आर्थिक लाभ होगा, जिससे दो लाख से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि में मंत्री श्री वाघाणी ने कहा कि देश की चीनी समितियां आम तौर पर गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भारत सरकार द्वारा तय किए गए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के हिसाब से कीमतों का भुगतान करती हैं। गुजरात की सहकारी चीनी समितियों ने केवल चीनी ही नहीं, बल्कि मोलासिस, इथेनॉल और को-जनरेशन द्वारा बिजली उत्पादन जैसे बाय-प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली आय का अधिकतम लाभ भी किसानों तक पहुंचाया है। इसके परिणामस्वरूप, गुजरात के गन्ना उत्पादक किसानों को देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमेशा अधिक कीमतें मिली हैं।

सहकारिता मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि अतीत में आयकर विभाग ने एफआरपी से अधिक कीमतों को मुनाफा मानते हुए गुजरात की विभिन्न चीनी सहकारी समितियों को टैक्स की डिमांड नोटिस भेजी थी। वर्ष 2007-08 से 2014-15 की अवधि से संबंधित इस जटिल मुद्दे के कारण राज्य की चीनी सहकारी समितियों पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ने की स्थिति पैदा हो गई थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से वर्ष 2023 में आयकर कानून के प्रावधानों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इन सुधारों के अनुसार, आयकर के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई गन्ने की कीमतों को मान्यता देने का कानूनी प्रावधान किया गया।

श्री पटेल ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए इस सुधार की रोशनी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य स्तर पर सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात सरकार ने चीनी सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान किसानों को चुकाई गई गन्ने की कीमतों को आधिकारिक स्वीकृति देने का क्रांतिकारी किसान हितैषी निर्णय किया है।

इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री का चीनी सहकारी समितियों और किसानों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए श्री वाघाणी ने यह साफ किया कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। वर्तमान में राज्य की चीनी सहकारी समितियां दो लाख से अधिक गन्ना उत्पादक किसानों को सीधे भुगतान करके किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सहकारी क्षेत्र के आधार को और भी मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

झुलसती धूप में भी बरकरार रहे चेहरे की चमक, घरेलू नुस्खों से पाएं नैचुरल निखार -शहनाज़ हुसैन

गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, उमस और प्रदूषण का असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखाई देने लगता है। खासतौर पर चेहरे की त्वचा धूप की अल्ट्रा वायलेट किरणों के संपर्क में आकर काली पड़ने लगती है, जिससे चेहरे की प्राकृतिक चमक फीकी हो जाती है। कई लोग घर से बाहर निकलते समय चेहरे को कपड़े से ढकते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप से बचने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद टैनिंग की समस्या पूरी तरह टल नहीं पाती। समुद्र तटों पर घूमने, लंबे समय तक बाहर रहने या रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण त्वचा पर धूप का प्रभाव बढ़ जाता है और चेहरा बेजान व डल दिखने लगता है। ऐसे में लोग अक्सर बाजार में मिलने वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। हालांकि हर उत्पाद हर त्वचा के लिए उपयुक्त नहीं होता और कई बार इनसे एलर्जी, जलन या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज़ हुसैन के अनुसार, प्राकृतिक घरेलू उपाय त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए टैनिंग दूर करने और चेहरे की खोई चमक वापस लाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। पपीता गर्मियों में त्वचा के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि धूप में रहने के कारण चेहरा काला पड़ गया हो तो पका हुआ पपीता त्वचा को फिर से निखार देने में मदद करता है। इसके लिए पपीते को मैश कर उसमें नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है। सूखने के बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लेने पर त्वचा धीरे-धीरे साफ और मुलायम दिखने लगती है। पपीते में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम मृत त्वचा को हटाने में मदद करते हैं, जबकि नींबू त्वचा की रंगत को हल्का करने का काम करता है। पपीते के साथ शहद का मिश्रण भी सन टैन हटाने में कारगर माना जाता है। पपीते में शहद मिलाकर बनाया गया फेस पैक त्वचा को पोषण देता है और उसे कोमल बनाए रखता है। नियमित उपयोग से चेहरे की थकी हुई त्वचा में नई चमक आने लगती है।

नींबू भी त्वचा की रंगत सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चम्मच नींबू का रस, शहद और दूध मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ और चमकदार दिखाई देने लगती है। दूध में मौजूद प्राकृतिक वसा और खनिज त्वचा को पोषण देते हैं, जबकि शहद त्वचा की नमी बनाए रखता है। इसी तरह चीनी और नींबू के रस से तैयार स्क्रब मृत त्वचा हटाने में सहायक होता है। इसे हल्के हाथों से चेहरे पर लगाने से त्वचा की गंदगी साफ होती है और चेहरा फ्रेश महसूस होता है।

गर्मियों में खीरा त्वचा के लिए किसी प्राकृतिक कूलेंट से कम नहीं माना जाता। इसका ठंडा और शांत प्रभाव त्वचा को तुरंत राहत देता है। खीरे का रस, गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा को ताजगी मिलती है और टैनिंग कम होने लगती है। खीरे में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा की रंगत निखारने में मदद करते हैं। आंखों पर खीरे की स्लाइस रखने से भी थकान कम होती है और त्वचा तरोताजा महसूस करती है।

जई का आटा और मठ्ठा भी गर्मियों में त्वचा को साफ और मुलायम बनाए रखने के लिए उपयोगी घरेलू उपाय माने जाते हैं। दोनों को मिलाकर तैयार पेस्ट चेहरे पर लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और अतिरिक्त तेल हटता है। वहीं केला, शहद और ऑलिव ऑयल का मिश्रण त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करता है। यह फेस पैक खासतौर पर रूखी और धूप से प्रभावित त्वचा के लिए लाभकारी माना जाता है।

एलोवेरा को त्वचा के लिए प्राकृतिक वरदान माना जाता है। एलोवेरा जेल में हल्दी और शहद मिलाकर लगाया जाए तो यह त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ टैनिंग कम करने में मदद करता है। एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट रखता है और उसकी प्राकृतिक चमक बनाए रखने में सहायक होता है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा की रंगत धीरे-धीरे साफ होने लगती है।

बेसन, दही और हल्दी का पारंपरिक उबटन भी गर्मियों में बेहद प्रभावी माना जाता है। बेसन त्वचा की गंदगी साफ करता है, दही त्वचा को मुलायम बनाता है और हल्दी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का काम करती है। यह मिश्रण त्वचा को साफ, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। एक अन्य प्रभावी घरेलू फेस पैक में कद्दूकस किया हुआ खीरा, कच्चा दूध, एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है। यह पैक त्वचा को गहराई से ठंडक देता है और नियमित उपयोग से धीरे-धीरे टैनिंग कम होने लगती है। त्वचा विशेषज्ञों का कहना है कि केवल फेस पैक लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि त्वचा की नियमित देखभाल भी जरूरी है। दिन में दो से तीन बार चेहरे को ठंडे पानी से धोने से धूल, पसीना और गंदगी साफ होती है। सप्ताह में एक या दो बार हल्का स्क्रब करने से डेड स्किन हटती है और चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आता है। हालांकि स्क्रब करते समय चेहरे को ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।इसके अलावा गर्मियों में त्वचा को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। दिन में दो बार मॉइश्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बनी रहती है और रूखापन कम होता है। पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और तेज धूप में निकलते समय चेहरे को ढकना भी त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के पास न्यू मेंटल कैंपस में 105 करोड़ रुपए के खर्च से अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्टल और कैंटीन ब्लॉक बनाए जाएंगे : स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया

अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुए 'अतुल्यम 1 से 4 ब्लॉक' के नुकसान के एवज में टाटा एयरलाइंस स्वास्थ्य विभाग को 53.12 करोड़ रुपए चुकाएगी : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया

गांधीनगर : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में सिविल हॉस्पिटल-असारवा के पास स्थित न्यू मेंटल कैंपस में हुए 'अतुल्यम 1 से 4 ब्लॉक' के नुकसान के एवज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टाटा एयरलाइंस से 53.12 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जिसके संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए टाटा एयरलाइंस आगामी समय में स्वास्थ्य विभाग को 53.12 करोड़ रुपए की पूरी राशि चुकाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि गत 12 जून 2025 को मेघाणीनगर में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश विमान दुर्घटना के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधीन 'अतुल्यम 1 से 4' ब्लॉक, कैंटीन और सब-स्टेशन बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ था। दुर्घटना के समय इस हॉस्टल में कुल 92 विद्यार्थी रह रहे थे। विमान दुर्घटना के बाद किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में इन बिल्डिंग्स को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के कारण उन्हें तोड़ने की मजबूरी बनी। ऐसे में विद्यार्थियों की रहने की सुविधा बाधित न हो और उनके हित में तत्काल नया हॉस्टल बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

सिविल अस्पताल कैंपस के पास बनने वाले नए आधुनिक हॉस्टल के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल-असारवा के पास स्थित न्यू मेंटल कैंपस में डॉक्टरों के लिए अनुमानित 105 करोड़ रुपए के खर्च से नया अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी हॉस्टल बनाया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी की नई 48 सीटों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन वर्षों के कुल 144 विद्यार्थियों सहित कुल 236 सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यू मेंटल कैंपस-आईजीपी कंपाउंड, मेघाणीनगर में नए सुपर स्पेशियलिटी हॉस्टल ब्लॉक के अलावा एक आधुनिक कैंटीन ब्लॉक और नया सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त जमीन भी आवंटित कर दी गई है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने आगे कहा कि इस कार्य को अधिक गति देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुमानित 51.84 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले 34.65 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था मंजूर की गई है। आगामी समय में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

अतुल्यम हॉस्टल की संरचना

नव नियोजित 'अतुल्यम 1 से 7' पीजी हॉस्टल जी+8 मंजिला संरचना के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 236 सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक फ्लैट को स्टूडियो अपार्टमेंट शैली में तैयार किया जाएगा, जिसमें एक लिविंग रूम-अटैच किचन, एक बेडरूम और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा सुरक्षा और प्राथमिक सुविधाओं जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम, आरओ प्लांट और सुदृढ़ ड्रेनेज व्यवस्था का भी समावेश किया गया है।

विद्यार्थियों की सुख सुविधाओं के लिए हॉस्टल कैंपस में पार्किंग हेतु विशाल बेसमेंट तथा अविवाहित पीजी विद्यार्थियों के लिए अलग आवास, अत्याधुनिक मेस, जिम, रिक्रिएशन रूम और आकर्षक लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाओं की भी योजना बनाई गई है।

सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद की सर्वे एवं निर्माण संस्था को सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन परियोजना के साथ-साथ लोथल स्थित नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्पलेक्स (NMHC) एवं धोलेरा एयरपोर्ट तक ब्रांच लाइन निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 134 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 220 किमी प्रति घंटा की डिज़ाइन स्पीड के अनुरूप किया जाएगा।

परियोजना के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा निर्माण निविदा में रुचि रखने वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा S & T (सिग्नल एवं दूरसंचार) क्षेत्र के संभावित बीडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

यह बैठक दिनांक 28 मई 2026 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) कार्यालय, 2nd फ्लोर, निर्माण भवन, नरोडा रोड, जीएससी हॉस्पिटल के सामने, असारवा अहमदाबाद में आयोजित होगी।

इस बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन, पैकेजिंग एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

सभी इच्छुक एवं संभावित बीडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स से अनुरोध है कि वे अपने मूल्यवान सुझावों एवं विचारों के साथ बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित करें।

जूनागढ़ शहर को मिलेगी बड़ी राहत: रेलवे बोर्ड ने ग्रोफेड में नए मीटर गेज स्टेशन को दी स्वीकृति; समपार फाटकों पर रोज़ाना के जाम से मिलेगी मुक्ति

जूनागढ़ शहर के नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत विसावदर–जूनागढ़ मीटर गेज खंड पर ग्रोफेड क्षेत्र में नए मीटर गेज स्टेशन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शहर के बीच की मीटर गेज लाइन होगी स्थायी रूप से बंद

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्रोफेड स्टेशन चालू होने के बाद ग्रोफेड और वर्तमान जूनागढ़ स्टेशन के बीच लगभग 4.2 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेलखंड स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यह रेलखंड वर्तमान में शहर के घनी आबादी वाले हिस्से से होकर गुजरता है और इसके कारण 7 समपार फाटक लंबे समय तक बंद रहते हैं, जिससे पूरे शहर में गंभीर यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के भीतर स्थित सभी 7 समपार फाटक समाप्त हो जाएंगे, जिससे जूनागढ़ शहर

को लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

नागरिकों को होने वाले प्रमुख लाभ

ट्रैफिक जाम से मुक्ति

मीटर गेज लाइन बंद होने के साथ शहर के भीतर स्थित सभी 7 समपार फाटक समाप्त हो जाएंगे। इससे नागरिकों, स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों तथा आपातकालीन सेवाओं को बार-बार होने वाले जाम से राहत मिलेगी।

घनी आबादी वाले क्षेत्र से 7 समपार फाटकों के समाप्त होने से सड़क एवं रेल दुर्घटनाओं की संभावना में उल्लेखनीय कमी आएगी।

समपार फाटकों के संचालन एवं रखरखाव में लगे रेलवे कर्मचारियों का बेहतर उपयोग अन्य परिचालन कार्यों में किया जा सकेगा।

जूनागढ़ नगर निगम द्वारा नए ग्रोफेड स्टेशन और वर्तमान जूनागढ़ स्टेशन के बीच ई-बस सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे मीटर गेज यात्रियों को ब्रॉड गेज ट्रेनों एवं शहर के अन्य हिस्सों तक सुविधाजनक संपर्क प्राप्त होगा।

वर्तमान जूनागढ़ स्टेशन पर मीटर गेज परिचालन समाप्त होने के बाद उपलब्ध भूमि का उपयोग ब्रॉड गेज यार्ड एवं अन्य परिचालन सुविधाओं के विस्तार हेतु किया जाएगा। रेलवे की यह पहल परिचालनिक आवश्यकता एवं नागरिक सुविधा — दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि जूनागढ़ के शहरी विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता एवं स्वच्छता अभियान आयोजित

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक उपयोग में कमी लाने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान एवं विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मंडल द्वारा 15.05.2026 से 05.06.2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों, संविदा कर्मियों तथा स्टॉल संचालकों को स्वच्छता एवं सतत विकास के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर 15.05.2026 से 19.05.2026 तक "स्वच्छता शपथ" कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों ने स्वच्छता बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। यात्रियों को प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करने एवं यात्रा के दौरान अपनी स्वयं की पानी की बोतल साथ रखने के लिए जागरूक किया गया।

रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं प्रसारित कर यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक उपयोग कम करने, स्वयं की पानी की बोतल उपयोग करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। रेलवे अधिकारियों द्वारा स्टॉल संचालकों एवं विक्रेताओं को गैर-प्लास्टिक एवं पर्यावरण अनुकूल कट्लरी अपनाने हेतु परामर्श भी दिया गया। दिनांक 19.05.2026 से 22.05.2026 तक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। प्लेटफॉर्मों पर कचरा पृथक्करण व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान संचालित किए गए तथा यात्रियों को कचरे के उचित निस्तारण के प्रति जागरूक किया गया। इन अभियानों में स्थानीय समुदायों एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भी सहभागिता रही। रेलवे कर्मचारियों को विशेष रूप से प्लास्टिक उपयोग में कमी एवं जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर संवेदनशील बनाया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 23.05.2026 से 26.05.2026 तक "प्लास्टिक न्यूनीकरण एवं सतत प्रथाएं" विषय पर विशेष अभियान चलाए गए। रेलवे स्टेशनों पर स्थापित प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों के रखरखाव एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। साथ ही, स्टेशनों पर विक्रेता स्टॉलों का निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी अनुपालन की निगरानी की गई।

रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध वॉटर कूलर सुविधाओं का निरीक्षण कर यात्रियों को अपनी बोतल पुनः भरने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे एकल उपयोग प्लास्टिक बोतलों की खपत कम हो सके। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों से प्लास्टिक बोतलों एवं अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के सीमित उपयोग हेतु सहयोग की अपील की गई तथा इस संबंध में यात्रियों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया।

कैटरिंग एवं ट्रेन सेवा प्रदाताओं को वर्जिन प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर पुनर्चक्रित एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित कर प्लास्टिक प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल भी की गई।

इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं एवं कर्मचारियों को दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग थैलियों को आंशिक रूप से काटने के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया, ताकि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। पर्यावरण माह के अंतर्गत स्वच्छता अभियान लगातार जारी हैं। अहमदाबाद मंडल पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं सतत विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सभी यात्रियों एवं हितधारकों से स्वच्छ एवं हरित वातावरण निर्माण में सक्रिय सहभागिता की अपील करता है।

मई - 2026 का मुख्यमंत्री का ऑनलाइन स्वागत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम 29 मई शुक्रवार को आयोजित होगा

▸▸ गुरुवार 28 मई की सार्वजनिक छुट्टी के कारण राज्य स्वागत कार्यक्रम में बदलाव किया गया

गांधीनगर : राज्य के नागरिकों की समस्याएं तथा प्रस्तुतियों के ऑनलाइन निवारण का प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाने वाला मुख्यमंत्री का राज्य स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम इस बार 29 मई, शुक्रवार के दिन आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने गुरुवार 28 मई की घोषित की गई बकरी ईद की सार्वजनिक छुट्टी के अनुसंधान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का मई-2026 का राज्य स्वागत गुरुवार के बजाय 29 मई को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

इस राज्य स्वागत कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता 29 मई शुक्रवार को सुबह 8 से 11 बजे तक अपनी समस्या मुख्यमंत्री के जनसंपर्क इकाई स्वर्णिम संकुल-2 गांधीनगर में प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को 29 मई को दोपहर के बाद राज्य स्वागत कार्यक्रम में प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर नागरिकों के प्रस्तुतियां सुनेंगे तथा प्रस्तुतियों के निवारण-समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे।

उमरेठ मत क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्री हर्षदभाई परमार ने विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के समक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की विशेष उपस्थिति

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की विशेष उपस्थिति में गुजरात विधानसभा की उमरेठ सीट पर हाल ही में आयोजित उप चुनाव में नवनिर्वाचित विधायक श्री हर्षदभाई गोविंदभाई परमार ने मंगलवार को गांधीनगर में विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के समक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस शपथ विधि समारोह में विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, वैधानिक एवं संसदीय मामलों के मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल सहित राज्य

मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधायक उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में किया गया नियमित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा मुंबई सेंट्रल और काठगोदाम के बीच नियमित रेल संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित किया गया है। यह नियमित सेवा संशोधित ट्रेन संख्या 21907/21908 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में परिचालित की जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 21907 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नियमित सेवा 27 मई, 2026 से मुंबई सेंट्रल से प्रारंभ होगी, जबकि ट्रेन संख्या 21908 काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नियमित सेवा 28 मई, 2026 से काठगोदाम से प्रारंभ होगी।

ट्रेन संख्या 21907 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 10:55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:50 बजे काठगोदाम पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 21908 काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को काठगोदाम से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 21:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जं., बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी, किच्छा, लालकुआं तथा हल्द्वानी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल में आरक्षण कराने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि संशोधित ट्रेन संख्याओं को ध्यान में रखें, क्योंकि यह ट्रेन उपर्युक्त तिथियों से ट्रेन संख्या 21907/21908 के रूप में परिचालित की जाएगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पिता की कैंसर से मौत के बाद कल्पेश पटेल ने रासायनिक खाद छोड़ चुनी प्राकृतिक खेती की राह : आज देश में एक 'रोल मॉडल' के रूप में उभरे

- सूरत जिले की ओलपाड तहसील के सरस गांव निवासी कल्पेश पटेल ने पिता की मौत के बाद 2019 से शुरू की प्राकृतिक खेती
- कल्पेश 50 से अधिक किस्मों के केलों की खेती करते हैं, देश भर से किसान और कृषि वैज्ञानिक उनकी केले की खेती को देखने के लिए सरस गांव आते हैं
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर जैविक खाद अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है

गांधीनगर : कभी-कभी किसी संवेदनशील व्यक्ति के जीवन में घटित कोई घटना उसके पूरे जीवन को बदल देती है और फिर वह कुछ ऐसा करता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। सूरत जिले की ओलपाड तहसील के सरस गांव के किसान कल्पेश पटेल के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

कल्पेश पटेल सूरत स्थित फैक्ट्री में केमिकल ऑपरेटर के रूप में नौकरी करते हैं। उनके पिता रमणभाई पटेल की कैंसर से मौत होने के बाद कल्पेश पटेल के जीवन में एक नया मोड़ आया। पिता की कैंसर से मौत के बाद उन्होंने तय किया कि वह अपने खेत में अब कभी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहरीले कीटनाशकों को छोड़कर कल्पेश पटेल ने प्राकृतिक खेती अपना ली।

स्वभाव से प्रकृति प्रेमी कल्पेश पटेल ने 2019 से प्राकृतिक खेती का राह चुनी। उन्होंने गुजरात सरकार के कृषि विभाग की ओर से दी जाने वाली प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत बनाना सीखा। इस प्रकार उन्होंने जीवन में एक नई शुरूआत की।

केले की विभिन्न किस्मों की खेती और उत्पादन में बनें रोल मॉडल

कल्पेश पटेल को विरासत में करीब आठ बीघा जमीन मिली है। उन्होंने साढ़े तीन बीघा जमीन पर केले की 50 से अधिक किस्में उगाई हैं, जिनमें पूवन, आधापुरी, रस्थली, लाल केळ, ब्लू जावा, बरराई, महालक्ष्मी और इलायची केला आदि शामिल हैं।

केले की विभिन्न किस्मों के साथ-साथ उन्होंने उत्पादन में भी रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025 में उनके खेत में केले के एक गुच्छे का वजन 73 किलो था। आम तौर पर केले के एक गुच्छे का वजन 20 से 30 किलो के आसपास होता है। लेकिन, कल्पेश पटेल की बाड़ी में केले के गुच्छे का औसत वजन 30 किलो से अधिक होता है।

जीवन का मोड़ और नए प्रयोग

कल्पेश पटेल ने प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ने की वजह का खुलासा करते हुए कहा, "जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, तभी मेरे मन में यह विचार आया कि अब रासायनिक खाद के जहर से मुक्त होना पड़ेगा और धरती माता को भी इस जहर से मुक्त करना है। प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना होगा। जब पिताजी खेती करते थे, तब वे खेत में बहुत अधिक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते थे और उनके पूरे शरीर से उस दवा की दुर्गंध आती थी। चूंकि मैं खेती से जुड़ा नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ कहता भी नहीं था। लेकिन, जब उन्हें कैंसर हुआ और बाद में उनका निधन हुआ, तो इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया।"

प्राकृतिक खेती के फायदे बताते हुए कल्पेश पटेल ने कहा, "मैं पिछले सात वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। मैंने 'जंगल मॉडल' भी अपनाया है। मैं अपने खेत उत्पादों में वैल्यू एडिशन करता हूं और 'मेरा माल, मेरा भाव' के सिद्धांत से खेती और उपज की बिक्री करता हूं। प्राकृतिक खेती के कारण प्रति बीघा जमीन पर होने वाला 15 से 20 हजार रुपए का रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का खर्च बंद हो गया है। यही नहीं, मिट्टी की सेहत सुधरने से केले का बंपर उत्पादन होने लगा है। सालाना साढ़े तीन बीघा के खेत में केले की खेती से 10 से 12 लाख रुपए की आय होती है।"

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर जैविक खाद अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है।

राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में प्राकृतिक खेती को एक नई रफ्तार मिली है। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत भी गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक कृषि की दिशा में मोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

वैल्यू एडिशन कर बढ़ाई खेती की आय

गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेत उत्पादों की बिक्री के लिए एक प्रयोग शुरू किया है। गुजरात के विभिन्न शहरों में प्राकृतिक कृषि बाजार बनाए हैं, जहां प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद बेच सकते हैं। कल्पेश पटेल सूरत के वेसू स्थित कृषि बाजार में केला और अन्य उत्पाद बेचते हैं। इतना ही नहीं, यदि कच्चे केले नहीं बिक पाते, तो कल्पेश उन केलों से वेफर और पाउडर जैसे उत्पाद बनाते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन के जरिए उनकी आय बढ़ जाती है।

घर बैठे बेचते हैं देश भर में केले

कल्पेश पटेल का केले की प्राकृतिक खेती का संदेश देश भर में पहुंच गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके साथ वार्तालाप किया और कल्पेश पटेल की सफलता की कहानी को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कल्पेश को दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर मिलते हैं, जिसे वे पार्सल के जरिए संबंधित राज्य में भेजते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा मानसून 2026 की व्यापक तैयारी,मुंबई की लाइफलाइन उन्नत मानसून तैयारी उपायों के साथ पूरी तरह मुस्तैद

पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी मानसून सीजन के दौरान सुरक्षित एवं निर्बाध ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में व्यापक मानसून तैयारी कार्य किए गए हैं। इन समग्र उपायों का उद्देश्य भारी वर्षा के दौरान व्यवधानों को न्यूनतम करना तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि मानसून तैयारी एवं शमन के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर लंबे समय तक जलभराव अथवा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तथा मानसून के कारण कोई बड़ी सेवा बाधा नहीं आई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आगामी मानसून सीजन के दौरान निर्बाध ट्रेन सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु मिशन मोड पर कई लक्षित कार्य किए गए हैं। पुलियों, नालों एवं जल निकासी मार्गों की सफाई और गाद निकासी, रेलवे पटरियों के किनारे जमा मलबा एवं कचरा हटाना, नई जल निकासी प्रणालियों के निर्माण, अतिरिक्त जल निकासी पंपों की स्थापना तथा पेड़ों की छंटाई जैसी प्रमुख गतिविधियाँ व्यापक स्तर पर की गई हैं।

पश्चिम रेलवे ने मानसून परिचालन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें निवारक उपाय, आकस्मिक योजना तथा तकनीकी हस्तक्षेप शामिल हैं, ताकि व्यवधानों को न्यूनतम किया जा सके और रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

श्री विनीत ने पश्चिम रेलवे द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रमुख कदमों के बारे में विस्तार से बताया:

व्यापक जल निकासी कार्यः कुल 58 पुलियों एवं पुल जलमार्गों की सफाई का कार्य चिन्हित किया गया है, जिनमें से 90% कार्य पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार लगभग 60 किलोमीटर नालों की गाद निकासी एवं सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 50 किलोमीटर से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील स्थानों पर जल निकासी की सुगमता हेतु नए नाले एवं मैनहोल बनाए गए हैं।

बाढ़ नियंत्रण उपायः उपनगरीय खंड के संवेदनशील स्थानों पर कुल 126 उच्च क्षमता वाले जल निकासी पंप लगाए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक हैं। आपातकालीन उपयोग हेतु अतिरिक्त पंप भी रखरखाव डिपो में रणनीतिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

बाढ़ एवं वर्षा निगरानीः वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने हेतु 40 बाढ़ मापक यंत्र तथा 6 ऑटोमेटेड डिजिटल रेन गेज (ARG) रणनीतिक स्थानों पर लगाए गए हैं, जो वर्षा एवं जलस्तर की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं।

उन्नत जलस्तर निगरानीः संवेदनशील पुलों पर वास्तविक समय एवं प्रमाणिक जलस्तर जानकारी प्राप्त करने हेतु पश्चिम रेलवे ने मुंबई उपनगरीय खंड के महत्वपूर्ण स्थानों पर SCADA-आधारित जलस्तर निगरानी उपकरण स्थापित किए हैं, जो सतत निगरानी एवं समय पर चेतावनी सुनिश्चित करते हैं।

मलबा सफाई अभियानः पिछले मानसून से अब तक उपनगरीय खंड से मलबा, कचरा एवं निकाली गई मिट्टी हटाने हेतु मलबा विशेष ट्रेनों के लगभग 480 फेरे संचालित किए गए हैं। यह कार्य मलबा विशेष वैगनों, जेसीबी, पोकलेन मशीनों तथा श्रमिकों की सहायता से किया जा रहा है। इससे मानसून के दौरान वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित होती है।

आधुनिक तकनीक का उपयोगः पुलियों एवं नालों की सफाई के सर्वेक्षण एवं निगरानी हेतु ड्रोन तथा फ्लोटर कैमरा ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। चिन्हित स्थानों पर गहन सफाई के लिए विशेष सक्शन एवं डी-स्लजिंग मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है।

माइक्रो-टनलिंग एवं अतिरिक्त जल निकासीः वर्षा जल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए 1200 मिमी एवं 1800 मिमी व्यास की पाइपों द्वारा माइक्रो-टनलिंग कार्य किए जा रहे हैं। चर्चगेट-विरार खंड के बीच माइक्रो-टनल पाइप ओपनिंग्स की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जिससे जल निकासी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ट्रैक संरक्षा एवं संवेदनशील स्थान प्रबंधनः उपनगरीय खंड के बाढ़ संभावित एवं संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहाँ ट्रैक ऊँचाई बढ़ाने एवं अतिरिक्त जल निकासी व्यवस्था जैसे स्थान-विशिष्ट सुधारात्मक कार्य किए गए हैं।

वृक्ष प्रबंधनः तेज हवा एवं बारिश के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने तथा ट्रैक पर अवरोध से बचने के लिए पटरियों के समीप स्थित पेड़ों की छंटाई एवं हटाने का कार्य किया जा रहा है।

100 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त रेलकर्मी श्री उमेदभाई पटेल का वडोदरा मंडल द्वारा गरिमामय सम्मान

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रतापनगर में एक भावपूर्ण एवं गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री उमेदभाई बेचरभाई पटेल के शतायु जीवन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्री उमेदभाई बेचरभाई पटेल वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक कार्यालय, वडोदरा में अकाउंट असिस्टेंट पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने सेवाकाल में उन्होंने निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता के साथ रेलवे सेवा को समर्पित किया। उनके जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होना न केवल उनके परिवार बल्कि रेलवे परिवार के लिए भी गर्व एवं प्रेरणा का विषय है।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, वडोदरा श्री राजू भडके ने श्री पटेल को पुष्पगुच्छ, शॉल एवं प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएँ व्यक्त कीं। समारोह के दौरान वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री आर्य किर्णेन्दु ने भी श्री पटेल का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया तथा उनके स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की कामना की।

अपने संबोधन में श्री पटेल ने रेलवे सेवा के दौरान के अनेक प्रेरणादायक अनुभव एवं संस्मरण साझा किए। उन्होंने अपने कार्यकाल की स्मृतियों को उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बाँटते हुए अनुशासन, समर्पण एवं सकारात्मक जीवनशैली के महत्व पर प्रकाश डाला।

समारोह का वातावरण अत्यंत आत्मीय एवं प्रेरणादायी रहा। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री पटेल के स्वस्थ, सक्रिय एवं सम्मानपूर्ण जीवन को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक, वडोदरा श्री नीरज धमीजा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार सहित लेखा विभाग, वडोदरा के अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नेताओं की पेंशन रोकने और उस धन का उपयोग जनहित में करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार में मंदी, शिक्षा का निजीकरण, कॉरपोरेट कंपनियों जैसे महंगे निजी अस्पताल, रामभरोसे जैसे सरकारी अस्पताल और स्कूल - इन दिनों सरकार में बैठे पार्षदों से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, हर कोई जनता की सेवा की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो इन मंत्रियों और नेताओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता की कुर्सी पर बैठना और उसका स्वाद चखना है। चूंकि उन्हें बंगले, दफ्तर, गाड़ियां, बिजली, टेलीफोन, नौकर, पेट्रोल, रेल और हवाई यात्रा जैसी सभी जरूरी सुविधाएं अपने परिवार के साथ मुफ्त में मिलती हैं, इसलिए वे सत्ता नहीं छोड़ते। जनता की सेवा करना उनके लिए एक बहाना है। यह सब इसलिए चल रहा है क्योंकि जनता ही उन्हें अपने कंधों पर बिठा रही है।

अब बुनियादी बातों पर आते हैं। नेताओं को दी जाने वाली ये पेंशन बंद कर देनी चाहिए क्योंकि चुनाव लड़कर और सत्ता का आनंद लेकर अमीर बने ये आधुनिक अंग्रेज उनके माता-पिता जैसे नहीं हैं। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के बंगले, लाखों की महंगी गाड़ियां आदि होने के बावजूद, जब वे सेवानिवृत्त होते हैं (चाहे दो कार्यकाल हारने के बाद या चुनाव जीतकर करोड़ों कमाने और स्वेच्छा से राजनीति छोड़ने के बाद), तो उन्हें भारी पेंशन मिलती है। महंगाई के कारण यह जनता के लिए एक बड़ा झटका है। वे जनता के करों से पेंशन वापस भी लेते हैं। इस प्रकार, सत्ता में रहने और सत्ता छोड़ने के बाद भी, उनकी पेंशन एक तरह का आराम बनी रहती है। इन सभी सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए।

यहाँ मुद्दा यह है कि इन प्रभावशाली लोगों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए। यह पेंशन सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा है। अगर नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए, तो हर साल करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं। सरकार इस बची हुई रकम को अन्य क्षेत्रों में निवेश कर जन कल्याणकारी कार्यों में लगा सकती है। जैसे सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकारी स्कूल बनवाना, अच्छी सड़कें और पुल बनवाना आदि। पेंशन से बची हुई रकम का इस्तेमाल इन कार्यों में किया जा सकता है।

और अंत में, सत्ता में मौजूद सभी दलों के नेता, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, सरकारी पेंशन के लाभ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि सभी नेता केवल जनता की सेवा करने की बात करते हैं। जब देश के हित में कुछ त्यागने की बात आती है, तो वे सब चुप हो जाते हैं। यानी, हर कोई सरकारी भेस में नागा है।

चाहे बीते दौर के नेता हों या सेवा करने के इच्छुक नए युवा, वर्तमान नेताओं में से एक ऐसा नेता है जो उनके लिए आदर्श बन सकता है। वह नेता जो देश के हित में बिना पेंशन लिए जीवन भर जनता की सेवा करने का संकल्प लेता है और जनता के धन को महत्व देते हुए सरकारी सुविधाओं से दूर रहने की सार्वजनिक घोषणा करता है, वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो? जनता की सेवा के नाम पर नेता मौज-मस्ती करते हैं और करोड़ों रुपये के लिए खेलते हैं। इससे जनता का धन जनता के हित में उपयोग होने से रुक जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि यदि 1 अप्रैल, 2004 के बाद 35-38 वर्षों तक सरकारी सेवा में रहे लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, जिससे उनके पिछले जीवन की आय का आधार छीन लिया गया है और उन्हें पेंशनभोगी बना दिया गया है, तो पांच वर्षों तक चुनाव जीतने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले और पेंशन प्राप्त करने वाले नेताओं की पेंशन भी रोक दी जानी चाहिए।

इस संबंध में, विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, छगनलाल दौलतराम मेवाड़ा, जनहित में नेताओं की पेंशन रोकने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को एक लिखित पत्र सौंपेंगे और पेंशन रोकने तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे।

वडोदरा मंडल में मंडल राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राजू भडके की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन दिनाँक 25 मई, 2026 को किया गया। इस अवसर पर हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जयंती भी मनाई गयी एवं राजभाषा प्रश्न-मंच का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने अपने कर कमलों से हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। इसके उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महोदय द्वारा मूल हिंदी टिप्पण आलेखन पुरस्कार योजना 2024-25 के विजेता कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने कहा कि सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारा संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने सभी शाखा अधिकारियों से सरल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को पत्राचार एवं ई-ऑफिस में हिंदी नोटिंग प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में पत्राचार, नोटिंग तथा फाइलों एवं रजिस्टरों में द्विभाषी शीर्षकों का उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी कार्यालयों में हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रबड़ मोहरों एवं नाम पट्टों के प्रयोग के निर्देश भी दिए। श्री नवीन यादव, प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) एवं मंडल संरक्षा अधिकारी द्वारा दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की गई तथा वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 पर चर्चा की गई। उन्होंने हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन एवं हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेल विषयक राजभाषा प्रश्न-मंच का संचालन भी किया। प्रश्न-मंच के विजेताओं को स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ अनुवादक श्री गुरु प्रसाद जोशी द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित मंडल के वरिष्ठ शाखा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सोना वायदा में 1292 रुपये और चांदी वायदा में 5618 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा में 269 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 516719.54 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 29179.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 487539.88 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2624.51 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 18747.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 158789 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158789 रुपये और नीचे में 157735 रुपये पर पहुंचकर, 159081 रुपये के पिछले बंद के सामने 1292 रुपये या 0.81 फीसदी घटकर 157789 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 922 रुपये या 0.72 फीसदी लुढ़ककर 126524 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 152 रुपये या 0.95 फीसदी लुढ़ककर 15789 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 158120 रुपये के भाव पर खूलकर, 158150 रुपये के दिन के उच्च और 157225 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1196 रुपये या 0.75 फीसदी लुढ़ककर 157319 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 158299 रुपये के भाव पर खूलकर, 158299 रुपये के दिन के उच्च और 157244 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158506 रुपये के पिछले बंद के सामने 1103 रुपये या 0.7 फीसदी लुढ़ककर 157403 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 274727 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 274727 रुपये और नीचे में 269913 रुपये पर पहुंचकर, 276716 रुपये के पिछले बंद के सामने 5618 रुपये या 2.03 फीसदी गिरकर 271098 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 5356 रुपये या 1.91 फीसदी गिरकर 275058 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 5291 रुपये या 1.89 फीसदी की गिरावट के साथ 275080 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 29179.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 487539.88 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 18747.33 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

मेटल वर्ग में 4514.74 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 6.55 रुपये या 0.49 फीसदी गिरकर 1341 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मई वायदा 30 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 374.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 75 पैसे या 0.19 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 387.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 1.05 रुपये या 0.52 फीसदी की मजबूती के साथ 204.4 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5830.86 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8778 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8980 रुपये और नीचे में 8749 रुपये पर पहुंचकर, 269 रुपये या 3.12 फीसदी बढ़कर 8895 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 268 रुपये या 3.11 फीसदी की मजबूती के साथ 8895 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 279.9 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 283.5 रुपये और नीचे में 278.4 रुपये पर पहुंचकर, 277.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.5 रुपये या 0.9 फीसदी की तेजी के संग 280 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 2.2 रुपये या 0.79 फीसदी की तेजी के संग 279.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 959 रुपये पर खूलकर, 90 पैसे या 0.09 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 955.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 10339.89 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8407.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3057.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 782.85 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 27.03 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 637.76 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन सिंों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3909.30 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1903.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9772 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 65406 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20001 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 324185 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 49673 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10192 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 25722 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 84206 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15383 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 23186 लोट के स्तर पर था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 44.3 रुपये की बढ़त के साथ 277.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.45 रुपये की बढ़त के साथ 14.55 रुपये हुआ। सोना मई 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 410 रुपये की गिरावट के साथ 162.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 275000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3174 रुपये की गिरावट के साथ 331 रुपये हुआ। तांबा जून 1450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.74 रुपये की गिरावट के साथ 8.3 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.83 रुपये की गिरावट के साथ 6.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 85.3 रुपये की गिरावट के साथ 246.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.7 रुपये की गिरावट के साथ 14.2 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 44 रुपये की बढ़त के साथ 146 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 265000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 80.5 रुपये की बढ़त के साथ 217.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.34 रुपये की बढ़त के साथ 10.42 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.17 रुपये की गिरावट के साथ 6.16 रुपये हुआ।